अमर उजाला
75
महोत्सव विश्वास का
• 6 राज्य
• 2 केंद्रशासित प्रदेश
• 22 संस्करण
राजधानी •
वर्ष 21 | अंक 206 | पृष्ठ : 20+6+16 | मूल्य : चार रुपये

अमर उजाला

नई दिल्ली
बृहस्पतिवार, 2 नवंबर 2023
कार्तिक कृष्ण-पंचमी
विक्रम संवत-2080

विश्वकप | विजय रथ पर सवार भारत की नजर जीत की सत्ता कायम रखने पर...स्पोर्ट्स | दिल्ली-एनसीआर

नोएडा एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में बसाई जाएगी जापानी टाउनशिप

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-32 और सेक्टर-10 में जमीन की चिह्नित

माई सिटी रिपोर्टर

इसी माह आएगी भूखंड योजना
प्रत्येक कंपनी को कम से कम 100 करोड़ का करना होगा निवेश

ग्रेटर नोएडा। विदेशी निवेश नीति बनने के बाद यमुना प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में जापानी टाउनशिप बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें एक ही परिसर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जापान की 11 कंपनियों ने क्षेत्र का दौरा कर जमीन चिह्नित करा दी है। जल्द ही इस टाउनशिप के लिए योजना भी लांच कर दी जाएगी।

दरअसल, लखनऊ में हुए वैश्विक निवेश सम्मेलन में जापान के औद्योगिक समूह की ओर से एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ भूमि पर जापानी सिटी बसाने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि एफडीआई पालिसी नहीं बनने के कारण मामला अधर में था। अब सरकार ने एफडीआई पालिसी बना दी है। जिसके बाद जापान के औद्योगिक समूहों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिलकर एक बार फिर प्रस्ताव दिया गया। शासन के निर्देश पर यीडा ने 500 एकड़ भूमि सेक्टर-10 और सेक्टर-32 में चिह्नित की है। इसमें सेक्टर-32 में 500 एकड़ भूमि दी जाएगी। यहां पर सेमीकंडेक्टर, चिप, कैमरा, एआई इक्यूपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली कंपनियां आएंगीं। विदेशी कंपनियां यहां 1000 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी। इससे पांच हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। 15 नवंबर के बाद सशर्त एक योजना लाई जाएगी, जिसमें केवल जापान की कंपनी ही भाग ले सकेंगी। सेक्टर-10 और सेक्टर-32 में जिस जमीन पर यह योजना लाई जाएगी, वहां पर जमीन की जांच भी कराई जा चुकी है।

> वैश्विक निवेश सम्मेलन में जापान की कंपनियों ने यहां पर उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की थी। अब एफडीआई पालिसी लागू होने के बाद जापान की 11 कंपनियों ने जमीन देखकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उनकी टाउनशिप के लिए जमीन लाई जाएगी। – **डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण**

इन कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों और अधिकारियों को सारी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए मिश्रित भू उपयोग की भी छूट दी जाएगी। इन कंपनियों को प्रदेश का जीएसटी नहीं देनी होगी और श्रमिकों के निवास पर 10 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। साथ ही आरएंडडी के लिए दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बिजली डयूटी पर भी पांच वर्ष तक 100 फीसदी छूट प्रदेश सरकार से मिलेगी और 500 लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति व्यक्ति हर माह पांच हजार रुपये भी सरकार देगी।

क्या है एफडीआई

भारत दूसरे देशों से निवेश लाने और यहां पर उनको स्थापित कराने के लिए सरकार ने एक नीति बनाई है। इस पूर्ण रूप से विदेशी निवेश लाने के लिए नीति बनाई है। इसे फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट या एफडीआई भी कहते हैं। इन कंपनियों को कम से कम 100-100 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा, तभी उनको यहां पर कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

सेक्टर-94 से पुश्ता रोड के ऊपर बनेगी एलिवेटेड रोड, जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा

नोएडा। सेक्टर-94 से पुश्ता रोड पर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इसकी तैयारी कर दी है। इस बाबत कुछ दिन पहले प्राधिकरण और प्रशासन के साथ एनएचएआई की बैठक हो चुकी है। इसमें विकल्प तलाशने को कहा गया है। दरअसल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के विकल्प तलाशने के लिए अधिकारी कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में हुई बैठक में पुश्ते के साथ की सड़क को एक्सप्रेसवे के तौर पर तैयार करने पर विचार मंथन हुआ। बैठक में जमीन की अड़चन दूर करने के लिए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने पर चर्चा हुई। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है। न्यू नोएडा के मास्टर प्लान 2041 में भी इसका जिक्र किया गया है। हालांकि इस बाबत अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। एयरपोर्ट से दिल्ली और नोएडा को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए भी यह जरूरी है क्योंकि वर्तमान एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव काफी ज्यादा है। इसके दूसरी ओर किसी तरह की सड़क बनाने का विकल्प मौजूद नहीं है क्योंकि दूसरी ओर सर्विस रोड के बाद मेट्रो का कॉरिडोर भी है। ऐसे में एक्सप्रेसवे के दाईं ओर ही विकल्प सही माना जा रहा है। अब इसके विकल्प के लिए अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर जायजा लेगी और विचार मंथन के बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। हालांकि यह तभी होगा जब इस परियोजना के लिए एकराय बन जाएगी। ब्यूरो

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तलाशेगा विकल्प